रिपोर्टेबल

भारत का सर्वोच्च न्यायालय

आपराधिक अपील क्षेत्राधिकार

आपराधिक अपील संख्या 2018/2013

[एस. एल. पी. (आपराधिक) संख्या 9278/ 2012 से उत्पन्न]

राजस्थान राज्य ..... अपीलार्थी

बनाम

शंभू केवट और एक अन्य ..... उत्तरदाताओं

निर्णय

के एस राधाकृष्णन, जे।

1. अनुमति अनुदत्त की गई।

2. प्रतिवादीगणों पर यहाँ भा.दं.सं. की धारा 307, 323, 325, 427 सपठित धारा 34 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए आरोप पत्र दायर किया गया था। उनका विचारण अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, फास्ट ट्रैक नं.1, कोटा, राजस्थान के समक्ष हुआ। अभियोजन पक्ष की ओर से, पीडब्लू 1 लगायत 5 को परीक्षित कराया गया और प्रदर्श P1 - P12 पेश किये गए। बचाव पक्ष की ओर से, दूसरे आरोपी को DW-1 के रूप में परीक्षित कराया गया।

सत्र न्यायालय ने पक्षकारों को सुनने और मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य पर विचार करने के पश्चात् अभियुक्त व्यक्तियों को भा.दं.सं. की धारा 307 के साथ पठित धारा 34 के अधीन दंडनीय अपराध का दोषी पाया, लेकिन अपने आदेश दिनांक 9.7.2009 के द्वारा उन्हें शेष आरोपों से दोषमुक्त कर दिया। बाद में, अभियुक्त व्यक्तियों को सजा के बिंदु पर सुना गया, और उन्होंने कहा कि वे आदतन अपराधी नहीं हैं और उनकी आयु क्रमशः 26 और 28 वर्ष है। इसके अलावा, यह बताया गया कि वे शादीशुदा गरीब मजदूर हैं और उनके बच्चे हैं। इसके अलावा, यह भी बताया गया कि चोटें अचानक उकसावे के कारण हुई थीं, और पूर्व-नियोजित नहीं थीं। अभियुक्त और अभियोजन पक्ष को सुनने के बाद, विचारण न्यायालय ने सजा पर निम्नलिखित आदेश पारित कियाः

> "दोनों पक्षों को सुना। उपरोक्त तर्कों के आधार पर, मामले की फाइल का अध्ययन किया। यद्यपि अभियोजन पक्ष द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध कोई आपराधिक अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया है और न ही आदतन अपराधी के बारे में कोई तर्क दिया गया है, तथापि, साक्ष्य से फाइल पर आया है, यह तथ्य स्थापित हो गया है कि अभियुक्त बनवारी और शंभू शिकायतकर्ता अब्दुल राशिद से उधारी पर माल ले रहे थे, घटना के दिन भी उधार पर माल लेने आये थे और बकाया पैसों के कारण, उसने उधार पर माल देने से इनकार

कर दिया। फिर वे घटना स्थल पर वापस आ गए। इसके लगभग 10 मिनट बाद में दोनों लोहे की छड़ और लोहे जैसी तलवार की एक पट्टी के साथ योजनाबद्ध तरीके से आए और दोनों ने मिलकर अब्दुल राशिद पर जानलेवा हमला किया। अब्दुल राशिद के सिर की हड्डी के टुकड़े के टूटने के बाद सिर पर घातक चोट पहुँचाकर, मस्तिष्क के अंदर चला गया। डॉक्टर ने सर्जरी की और उसे बाहर निकाला। इसके बाद यह नहीं कहा जा सकता है कि आरोपी अज्ञानता में घायल हो गया है, अचानक उकसाने पर और अब्दुल राशिद को उक्त चोट का कारण बना है और उनके द्वारा कार्य करने के लिए, उनका ऐसा कार्य करने का कोई इरादा या उद्देश्य नहीं है। आरोपी के खिलाफ भा.दं.सं. की धारा 307 के तहत मामला संदेह से परे साबित हुआ है। अतः इस स्थिति में अभियुक्त के विरुद्ध उदार दृष्टिकोण नहीं अपनाया जा सकता है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने कई मामलों में यह रुख प्रकट किया है कि यदि अभियुक्तों को नरमी दी जाती है, तो समाज में अपराधी लोगों को प्रोत्साहित किया जाएगा। आरोपियों ने अपनी दुकान में बैठे शिकायतकर्ता को बिना किसी कारण के घायल कर दिया था। यह दुकान में बैठे समाज के अन्य लोगों द्वारा देखा गया है। अभियुक्त के साथ उदार दृष्टिकोण अपनाने से

समाज के अन्य लोगों का विश्वास न्याय से उठ जाएगा। ऐसी स्थिति में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार, अभियुक्तों को निम्नानुसार दंडित किया जाता हैः

<u>सजा का आदेश</u>

इसलिए, अभियुक्त शंभू पुत्र बाबू लाल और अभियुक्त बनवारी लाल पुत्र बाबू लाल केवट, निवासीगण इकबाल चौक, सकटपुरा, कोटा को भा.दं.सं. की धारा 427 के तहत आरोप से दोषमुक्त घोषित किया जाता है और दोनों आरोपियों को भा.दं.सं. की धारा 307 सपठित 34 के तहत आरोप से दोषी ठहराया जाता है और 10-10 (दस) के लिए सजा सुनाई जाती है। जुर्माने के भुगतान में चूक करने की स्थिति में 3-3 महीने की अतिरिक्त साधारण कारावास का सामना करना पड़ेगा। आरोपी द्वारा पुलिस/न्यायिक हिरासत में बिताई गई अवधि को धारा 428 Cr.P.C के प्रावधान के तहत मूल सजा की अवधि में समायोजित किया जाएगा। सजा का वारंट तैयार किया जाए। मामले में बरामद संपत्ति, लोहे की सड़क और लोहे जैसी तलवार की पट्टी को अपील की सीमा समाप्त होने के बाद दिशा-निर्देशानुसार नष्ट कर दिया जाए। फैसले की प्रति अभियुक्तों को निःशुल्क प्रदान की जाए।"

3. दोषसिद्धि और सजा के आदेश से व्यथित, अभियुक्त व्यक्तियों ने उच्च न्यायालय में एस बी क्रिमिनल अपील संख्या 825/2009 दायर की। जब 16.11.2011 को अपील सुनवाई के लिए आई, तो शिकायतकर्ता अब्दुल राशिद, जो न्यायालय में मौजूद था, ने कहा कि उसने और आरोपी व्यक्तियों ने एक समझौता किया है और उस समझौते के आधार पर, उसने आरोपी व्यक्तियों से मुआवजे की राशि प्राप्त की। नतीजतन, यह बताया गया कि वह अपील को आगे नहीं बढ़ाना चाहता। शिकायतकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया कि चूंकि पक्षों ने मतभेदों को दफन कर दिया था और चूंकि किया गया अपराध 'राज्य के खिलाफ' के बजाय 'एक व्यक्ति के खिलाफ' था, इसलिए आरोपी व्यक्तियों को सलाखों के पीछे रखने से कोई सार्थक उद्देश्य पूरा नहीं होगा, और इसलिए, यह अनुरोध किया गया था कि मामले को शमन किया जाए और अपील को स्वीकार किया जाए।

4. हमने उच्च न्यायालय द्वारा बताए गए उस अनुरोध को अंगीकार करने के लिए कारणों की जांच की है। उच्च न्यायालय ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 और 320 के दायरे की जांच की और यह विचार व्यक्त किया कि समझौते के आधार पर किसी मामले को शमन करने और रद्द करने के बीच कुछ समानताएं और अंतर हैं और इसलिए, समझौते पर आपराधिक कार्यवाही को रद्द करना न्यायालय की विवेकाधीन शक्ति के भीतर है। यह भी राय दी कि जहां धारा 320 सीआरपीसी के तहत शक्ति

निहित, पाबंद और सीमित है, वहीं धारा 482 सीआरपीसी के तहत शक्ति विशाल, अद्वितीय और सर्वोपरि है। तथ्यों पर उच्च न्यायालय ने राय दी कि यह एक ऐसा मामला था जहां पक्षों के बीच लड़ाई पल भर की उत्तेजना में हुई थी और हमला 'बड़े पैमाने पर समाज के खिलाफ' के बजाय 'एक व्यक्ति के खिलाफ' अपराध था। उच्च न्यायालय ने निम्नलिखित निर्णय दियाः

> "वर्तमान मामले में, लड़ाई पल की गर्मी में पल की उत्तेजना में हुई। अभियोजन पक्ष के अनुसार, दोनों पक्ष मौखिक रूप से लड़ रहे थे जब आरोप लगाया गया कि अपीलकर्ताओं ने अब्दुल राशिद (पीडब्लू-3) को मारा। हमला बड़े पैमाने पर समाज के खिलाफ अपराध से अधिक एक व्यक्ति के खिलाफ अपराध था। निश्चितरूप से, दोनों पक्षों ने समझौता कर लिया है। उन्होंने अपने मतभेदों को सुलझा लिया है। इस प्रकार, अपील को स्वीकृति देना न्याय के हित में होगा।"

5. उच्च न्यायालय ने महसूस किया कि चूंकि पक्षों ने एक समझौता किया था और अपने विवादों और मतभेदों को हल कर लिया है, इसलिए अपील को स्वीकार करना न्याय के हित में होगा। नतीजतन, अपील को स्वीकार किया गया और आरोपी व्यक्तियों को भा.दं.सं. की धारा 307 सपठित 34 के तहत अपराध से दोषमुक्त कर दिया गया। इससे आहत होकर, इस अपील को प्राथमिकता दी गई है।

6. राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि उच्च न्यायालय ने गियन सिंह बनाम पंजाब राज्य और अन्य (2012) 10 SCC मामले में इस न्यायालय द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 और 320 के दायरे और साथ ही गैर-शमनीय अपराध में शामिल आपराधिक कार्यवाही को पक्षों के बीच हुए समझौते के आधार पर रद्द करने के लिए आपराधिक न्यायालय को प्रदत्त शक्तियां एवं निर्धारित विभिन्न सिद्धांतों को पूरी तरह से गलत समझा है। इस न्यायालय द्वारा निर्धारित विभिन्न दिशानिर्देशों की भी अनदेखी की गई। विद्वान वकील ने यह भी प्रस्तुत किया कि उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करने में भी त्रुटि की है कि जो अपराध साबित हुआ है वह केवल एक व्यक्ति के खिलाफ अपराध था, न कि राज्य के खिलाफ। विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि सत्र न्यायालय ने चोटों की प्रकृति को सही ढंग से देखा था और सही निष्कर्ष पर पहुंचा कि अभियुक्त ने अचानक उकसावे के कारण चोट नहीं पहुंचाई थी, बल्कि यह एक पूर्व नियोजित घटना थी और कि विचरण न्यायालय ने भा.दं.सं. की धारा 307 के तहत दंडनीय अपराध के लिए 10 साल के कठोर कारावास की सजा को सही ढंग से घोषित किया है।

7. दूसरी ओर, प्रतिवादी की ओर से पेश हुए विद्वान वकील ने तर्क दिया कि पक्षों ने एक समझौता किया था और समझौते के आधार पर, आरोपी व्यक्तियों ने शिकायतकर्ता को हुई चोटों के लिए पर्याप्त राशि का भुगतान किया और इस तथ्य ध्यान देते हुए की कथित अपराध पूर्व-ध्यान के बिना

पल भर के आवेश में किया गया था, उच्च न्यायालय द्वारा अपराध को शमन करने और आरोपी व्यक्तियों को दोषमुक्त करना न्यायोचित है।

8. हम यह इंगित कर सकते हैं कि गियन सिंह (उपर्युक्त) में, इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि अपराधी और पीड़ित के बीच समझौते के आधार पर अपराध या आपराधिक कार्यवाही को रद्द करना अपराधों के शमन के समान नहीं है। इस न्यायालय ने यह भी अभिनिर्धारित किया कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 320 के अधीन किसी न्यायालय को प्रदत्त अपराधों के शमन की शक्ति उच्च न्यायालय द्वारा आपराधिक कार्यवाहियों को निरस्त करने के लिए धारा 482 के अधीन प्रदत्त शक्ति से भौतिक रूप से भिन्न है। अपराधों के संयोजन में, आपराधिक न्यायालय की शक्ति दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 320 में निहित प्रावधानों द्वारा सीमित है और न्यायालय पूरी तरह से और स्पष्ट रूप से इसके द्वारा निर्देशित होता है, जबकि, दूसरी ओर, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत आपराधिक कार्यवाही या आपराधिक शिकायत को रद्द करने के लिए उच्च न्यायालय द्वारा राय का गठन रिकॉर्ड पर सामग्री द्वारा निर्देशित किया जाता है कि क्या न्याय के उद्देश्य शक्ति के ऐसे प्रयोग को उचित ठहराएंगे, हालांकि अंतिम परिणाम दोषमुक्ति या अभियोग की बर्खास्तगी हो सकती है।

9. न्यायालय ने यह भी राय दी कि अपने निहित अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए आपराधिक कार्यवाही या प्राथमिकी या शिकायत को रद्द करने में

उच्च न्यायालय की शक्ति दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 320 के तहत अपराधों को शमन करने के लिए आपराधिक न्यायालय को दी गई शक्ति से विशिष्ट और अलग है। इस न्यायालय ने आगे यह राय है की अंतर्निहित शक्ति की कोई वैधानिक सीमा नहीं है, लेकिन इसका उपयोग ऐसी शक्ति में निहित दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाना चाहिए, अर्थात्, (i) न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए, या (ii) किसी भी न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए। इस न्यायालय ने यह भी आगाह किया कि अपराध को शमन करने की शक्ति का प्रयोग करते समय, न्यायालय को अपराध की प्रकृति और गंभीरता का उचित सम्मान करना चाहिए।

10. इस मामले में, स्वीकार्य रूप से, हम नोटिस करते हैं, कि भा.दं.सं. की धारा 307 के तहत किया गया अपराध शमनीय नहीं है। ईश्वर सिंह बनाम राज्य M.P. (2008) 15 scc 667 में, अभियुक्त पर आईपीसी की धारा 307 के तहत दंडनीय अपराध करने का आरोप लगाया गया था और सीआरपीसी की धारा 320 के संदर्भ में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि खंड 307 एक शमनीय अपराध नहीं थी और धारा 320 में स्पष्ट मनाही थी कि यदि यह भा.दं.सं. के तहत शमनीय नहीं है तो किसी भी अपराध को शमन नहीं किया जाएगा। गुलाब दास और अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य (2011) 10 scc 765 में इस न्यायालय द्वारा एक अलग ध्यान आकर्षित किया गया, लेकिन भा.दं.सं. सी. की धारा 307 के तहत अपराध को शमन करने के कुछ कारण बताए गए थे। उस मामले में, इस

न्यायालय ने देखा कि घटना वर्ष 1994 में हुई थी और पक्षकार एक-दूसरे से संबंधित थे। घटना के समय दोनों आरोपी 20 वर्ष के थे। इसके अलावा, यह भी देखा गया कि शिकायतकर्ता के खिलाफ भी एक क्रॉस मामला दर्ज किया गया था जिसमें उसे दोषी ठहराया गया था और सजा सुनाई गई थी। इसके अलावा, यह भी देखा गया कि अभियुक्त व्यक्तियों को भी सजा की एक निश्चित अवधि से गुजरना पड़ा था। जिस मामले को पक्षों के बीच सुलझा लिया गया था, उसमें भा.दं.सं. की धारा 325 सपठित 34 और धारा 323 के तहत दंडनीय अपराध शामिल थे। ऐसी परिस्थितियों में न्यायालय ने महसूस किया कि पक्षकारों के बीच समझौता एक विवेकपूर्ण निर्णय था ताकि विवाद को शांत किया जा सके। अदालत ने दोषसिद्धि को बरकरार रखते हुए अभियुक्तों को दी गई सजा को उस अवधि तक कम कर दिया जो वे पहले ही भुगत चुके थे।

11. राजेंद्र हरकचंद भंडारी और अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य और एक अन्य (2011) 13 scc 311 में, इस न्यायालय के पास इस सवाल पर विचार करने का अवसर था कि क्या भा.दं.सं. की धारा 307 के तहत किसी अपराध को पक्षों के बीच हुए समझौते के संदर्भ में शमन किया जा सकता है। यह स्पष्ट रूप से अभिनिर्धारित किया कि भा.दं.सं. की धारा 307 के तहत अपराध दंड प्रक्रिया संहिता की खंड 320 (9) के संदर्भ में शमनीय नहीं है और इस तरह के अपराध का शमनीय होना प्रश्न से बाहर था। इसके अलावा, इस तथ्य पर ध्यान देते हुए कि घटना वर्ष 1991 में

हुई थी और तब से लगभग 20 साल हो चुके थे, और यह कि अभियुक्त व्यक्ति व्यवसाय से कृषक थे और उनकी कोई पूर्व आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं थी और पक्षों के बीच सुलह हुई थी, न्यायालय ने कहा कि न्याय के उद्देश्यों को पूरा किया जाएगा यदि अभियुक्त को दी गई मूल सजा को पहले से गुजर चुकी अवधि तक कम कर दिया जाए।

12. इस मामले में हम पाते हैं कि ऐसी स्थिति पैदा नहीं होती है। इस मामले में, घटना 30.10.2008 को हुई थी। विचारण न्यायालय अवधारित किया कि आरोपी व्यक्ति, समान इरादे से, उस दिन लोहे की छड़ और लोहे की एक पट्टी के साथ घायल अब्दुल राशिद की दुकान पर गए थे और अपने समान इरादे को आगे बढ़ाते हुए, अब्दुल राशिद के शरीर पर गंभीर चोटें कारित की, जिनमें से चोट संख्या 4 उसके सिर पर थी, जो गंभीर प्रकृति की थी।

13. डॉ. राकेश शर्मा, पीडब्लू-5 ने कहा था कि अब्दुल राशिद को हुई चोटों में से, चोट नं. 4 उसके सिर पर चोट लगी थी और वह चोट "गंभीर और जीवन के लिए घातक" थी। पीडब्लू-8, डॉ. उदय भोमिक ने भी यह कहा कि अब्दुल राशिद के सिर पर गंभीर चोट लगी थी। डॉ. उदय ने न्यूरो सर्जन के रूप में अब्दुल राशिद की चोटों पर ऑपरेशन किया और पीडब्लू 5 डॉ राकेश शर्मा द्वारा व्यक्त की गई राय का पूरी तरह से समर्थन किया कि चोट नं. 4 "जीवन के लिए गंभीर और घातक" थी।

14. हम देखते हैं कि चोटों की गंभीरता पर सत्र न्यायालय द्वारा ध्यान दिया गया था और उसने भा.दं.सं. की धारा 307 के तहत दंडनीय अपराध के लिए 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई थी, लेकिन उच्च न्यायालय द्वारा नहीं। उच्च न्यायालय ने गियन सिंह (उपर्युक्त) में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित विभिन्न सिद्धांतों की पूरी तरह से अनदेखी की है और यह विचार रखने में गलती की है कि अब्दुल राशिद के शरीर पर चोटें एक लड़ाई में लगी थीं जो उस समय के आवेश में हुई थी। इस न्यायालय द्वारा गियन सिंह (उपर्युक्त) में यह स्पष्ट रूप से अभिनिर्धारित किया गया है कि न्यायालय को, धारा 482 के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए, "अपराध की प्रकृति और गंभीरता" और "सामाजिक प्रभाव" को उचित रूप से ध्यान में रखना चाहिए। इन दोनों पहलुओं की उच्च न्यायालय द्वारा पूरी तरह से अनदेखी की गई। उच्च न्यायालय ने बिना सोचे समझे पक्षकारों के इस कथन को आंख मूंदकर स्वीकार कर लिया कि उन्होंने अपने विवादों और मतभेदों को सुलझा लिया है और यह विचार रखा कि यह "बड़े पैमाने पर समाज" के खिलाफ अपराध के बजाय "एक व्यक्ति" के खिलाफ अपराध था।

15. हम यह कहने के लिए तैयार नहीं हैं कि आरोपी व्यक्तियों द्वारा किया गया कथित अपराध एक व्यक्ति के खिलाफ अपराध था, दूसरी ओर यह बड़े पैमाने पर समाज के खिलाफ अपराध था। आपराधिक कानून को सामाजिक नियंत्रण प्राप्त करने के लिए एक तंत्र के रूप में तैयार किया गया है और

इसका उद्देश्य समाज के भीतर आचरण और गतिविधियों का विनियमन है। आईपीसी की धारा 307 को गैर-शमनीय क्यों माना जाता है, क्योंकि भा.दं.सं. ने पहचान की है कि किस आचरण को गैर-शमनीय अपराधों के दायरे में लाया जाना चाहिए। इस तरह के प्रावधान केवल व्यक्ति की रक्षा के लिए नहीं हैं, बल्कि पूरे समाज की रक्षा के लिए हैं। उच्च न्यायालय का यह सोचना सही नहीं था कि यह केवल व्यक्ति के लिए एक चोट थी और चूंकि अभियुक्त व्यक्तियों ने मौद्रिक मुआवजा प्राप्त किया था और मामले का निपटारा किया था, इसलिए उनके खिलाफ अपराध का सफाया कर दिया गया था। आपराधिक न्याय प्रणाली का एक बड़ा उद्देश्य है, जो कि बड़े पैमाने पर लोगों की सुरक्षा और संरक्षण है और यह न केवल अपराधी के लिए, बल्कि बड़े पैमाने पर व्यक्तियों के लिए एक सबक होगा ताकि इस तरह के अपराध किसी के द्वारा न किए जाएं और धन समाज के खिलाफ किए गए अपराध का विकल्प न हो। वर्तमान जैसे गंभीर अपराध पर उदार दृष्टिकोण रखने से आपराधिक न्याय प्रणाली के बारे में गलत धारणा बनेगी और आगे आपराधिक कृत्यों को प्रोत्साहित करना, जो बड़े पैमाने पर समाज के शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व और कल्याण को खतरे में डाल देगा।

16. इसलिए हम इस अपील को स्वीकार करते है और उच्च न्यायालय के फैसले को अपास्त करते हैं। उच्च न्यायालय समझौते से प्रभावित था और उसने गुण-दोष के आधार पर मामले की जांच नहीं की है, इसलिए हम उच्च न्यायालय को अपनी फाइल में अपील वापस लेने और गुण-दोष के

आधार पर अपील पर निर्णय लेने का निर्देश देते हैं। उच्च न्यायालय को छह महीने के भीतर अपील का निपटारा करने दें। तदनुसार आदेश दिया।

न्यायाधिपति (के एस राधाकृष्णन)

न्यायाधिपति (ए. के. सीकरी)

नई दिल्ली,

28 नवंबर, 2013

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" के जरिये अनुवादक की सहायता से किया गया है ।

अस्वीकरण- इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।